

प्रेषक,

मदन सिंह,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

रोका में,

अध्यक्ष,  
राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण,  
उत्तरांचल, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 21 फरवरी, 2006

विषय: वित्तीय वर्ष 2005-06 में अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक संख्या-3456-के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

संदर्भ,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-61/रा0आ0उ0सं0, दिनांक 31 जनवरी, 2006 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-581/XIX/बजट/2005-61/खाद्य/05, दिनांक: 07-4-2005, संख्या-716/XIX/बजट/05-61/खाद्य/2005, दिनांक: 02-5-2005, संख्या-1146/XIX/बजट/ 05-61/खाद्य/2005, दिनांक: 21-7-2005, संख्या-1215/XIX/ बजट/05-61/खाद्य/05, दिनांक: 30-9-2005, के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय खाद्य विभाग के राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण के अधिष्ठान मद के अन्तर्गत अध्यक्ष, राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण के आगारा के अनुक्षण हेतु संगत मद से रु0 1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) तथा संलग्न बी0एम0 15 के कॉलम-5 में अंकित रु0 50,000 (रुपये पचास हजार मात्र) के पुनर्विनियोग कर कुल 1.50 लाख की धनराशि आपके निर्वहन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों के आधार पर व्यय करने की राहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

1. उक्त धनराशि केवल उन्हीं मदों पर व्यय की जायेगी जिनके लिए यह स्वीकृति की जा रही है। किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों के क्रियान्वहन के लिए नहीं किया जायेगा।
2. स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तापुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर मरचेज रुल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।
3. यह सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय नहीं किया जायेगा जिसके लिए वित्तीय हस्तापुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो उस प्रकरण में व्यय के पूर्व यह प्राप्त कर ली जाय।
4. स्वीकृति की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथा आवश्यकतानुसार ही व्यय किया जायेगा तथा व्यय का विवरण यथा समय प्रत्येक मंद् बी0एम-13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।
5. उक्त मद मितव्ययता की मद है इसमें व्यय सीमित रखते हुए कटौती किये जाने का प्रयास किया जाय।
6. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-3456-सिविल पूर्ति-00-आयोजनेत्तर-001-निर्देशन तथा प्रशासन-04-उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित निदेशालय के अन्तर्गत प्रस्तर-1 में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामों खाता जायेगा।



7- यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-89/वि0अन0-5/2006 दिनांक 18 फरवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय  
(नन्दन सिंह)  
सचिव।

संख्या-27/6(1)/XIX/पुन0वि0/2006-61/खाद्य/2005, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तरांचल, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल देहरादून।
6. मुख्य कोषाधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून।
7. वरिष्ठ सम्भागीय वित्त लेखाधिकारी, खाद्य, गढ़वाल संभाग, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-5, उत्तरांचल शासन।
9. सगन्धक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(एन0सी0उप्र0सी0)  
अपर सचिव।

पुनर्विनिर्माण-2005-2006 विवरण पत्र

प्रारम्भिक दिग्ग- राज्य आयोग उपनोक्ता संरक्षण, निदेशक अधिकारी- सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।  
(धनराशि हजार रुपये में)  
आयोजनोत्तर से आयोजनोत्तर में

कृ.सं. क्रियाकलाप तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार माध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष धनराशि (सरलस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनिर्माण के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनिर्माण के बाद स्तम्भ-01 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुदान संख्या-25 अ.सं. संकेत पूर्ति 001-निर्देशन तथा संरक्षण प्रारम्भ-04-उपनोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित निदेशक	0	0	50(क)	42-अन्त व्यय-50	150	0	(क) स्तम्भ-1 में आवश्यकता नहीं है। (ख) नवनिर्माण अवधि के आवासीय अनुसंधान हेतु संगत मद में बजट व्यवस्था कम होने के कारण।
अ.सं. संकेत व्यय प्रतिपूर्ति -50	0	0	50	50	150	0	
कुल	50	0	50	50	150	0	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनिर्माण के बजट मैनुअल के परिच्छेद-150,151,155,156 में उल्लिखित प्रावधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

उप  
(समस्त/उपरी)  
अपर सचिव।